मधेशी समस्या व भारत नेपाल संबंध

प्रदीप,

शोध छात्र

परिचय

भारत से नेपाल का जुड़ाव ऐतिहासिक सांस्कृतिक भौगोलिक राजनीतिक व कई अन्य पक्षों से देखा जा सकता है। नेपाल भारत व चीन के बीच 18 से 50 किलोमीटर खुली सीमा है नेपाल का 60: से अधिक सार्वभौमिक व्यापार भारत में केंद्रित है तथा देश का लगभग आधा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत से होता है भारतीय विदेश नीति के सामरिक व सुरक्षा हित नेपाल से जुड़े थे।

भारत नेपाल संबंध ऐतिहासिक परिपेक्ष

यदि भारत नेपाल संबंध के ऐतिहासिक पर्यवेक्षक का अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि भारत व नेपाल के मध्य 1949 1950 के समय से अधिक सहयोग दिखाई देता है। सन 1950 में भारत नेपाल के मध्य शांति का संदेह राजा त्रिभुवन को कार्यकाल के समय में भारत समर्थन रुख अपनाया गया।

उनके स्थान पर नेपाल के राजा महेंद्र सत्तारूढ़ हुए तथा राजा महेंद्र के द्वारा भारत को संतुलित करने के लिए चीन कार्ड का प्रयोग किया गया। भारत की लोकतांत्रिक पंथनिरपेक्ष शासन प्रणाली एवं गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का प्रभाव प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में नेपाल में होता रहा है। सन 1960 में नेपाल में लोकतांत्रिक शासन का समाप्त कर दिया गया जिसका असर दोनों के संबंध पर स्पष्ट दिखाई देता है।

सन 1970 के दशक में भारत–नेपाल संबंधों में कटुता देखी जा सकती है जिसका मुख्य कारण सिक्किम का विलय था। भारत का परमाणु विस्फोट करना वह भारत सोवियत मैत्री भी मानी है राजीव गांधी के काल में नेपाल भारत के संबंध में कटुता चरम सीमा पर पहुंचे।

भारत–नेपाल संबंधों में कटुता के कारण

1. राजा महेंद्र व वीरेंद्र द्वारा समान दूरी का सिद्धांत अपनाया जाना
2. भारत द्वारा 1960 के समय नेपाल के प्रति आलोचनात्मक रवैया
3. सिक्किम का विलय परमाणु विस्फोट
4. राजीव गांधी का यथार्थवादी रवैया
5. भारत मैत्री सोवियत

मधेशी समस्या

वर्ष 2015 में नवीन संविधान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ व सितंबर खंड में इसे लागू कर दिया गया परंतु मद्धेशिया ने इससे अपने लिए भेदभाव पूर्ण माना मद्धेशिया ने अपने लिए 2 प्रांतों की मांग की क्योंकि नेपाल के 75 जनपद में से 22 जनपद में म देशों की बड़ी आबादी है 5 जनपद में मद्धेशिया को एक तरफा बहुमत मिली परंतु सन्यासियों के निर्माण के दौरान मधेशी बहुमत वाले जनपद को पहाडी क्षेत्र के साथ मोड़ दिया गया। प्रत्येक राज्य में पहाड़ी मैदान तथा तराई क्षेत्रों को शामिल किया गया जबकि मद्धेशिया तराई क्षेत्रों के लिए अलग मधेशी राज्य के निर्माण की मांग कर रहे थे।

संविधान में संसद की सीटों पर परिसीमन के लिए भाग को आधार बनाया गया जबकि

मवेशियों ने जनसंख्या के अनुसार संसदीय क्षेत्र के परिसीमन का समर्थन किया। संविधान में उच्च सदन में भारत राज्य को सम्मान प्रतिनिधि दिया गया जबकि मधेसी ने जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि की मांग की।

साथ ही यह भी किया गया कि जिन नेपाली नागरिकों के माता–पिता नेपाली हैं उन्हें ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया जाएगा जबकि मद्धेशिया के माता–पिता नेपाल के नागरिक नहीं है। किंतु गतिरोध को दिखाते हुए सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया और संसद में जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया। सरकार ने मधेशी समुदाय के लोगों के लिए शासन तथा सेना मे उचित प्रतिनिधि देने का प्रावधान किया परंतु मधेशी अभी भी अपने लिए 2 प्रांतों के निर्माण की मांग कर रहे हैं।

मद्धेशिया में भारतीय मूल के मधेशी व नेपाली मधेसी भी शामिल है। नेपाल की जनसंख्या 40ः भाग मधेशी क्षेत्रों में निवास करता है। नेपाल के राजस्व का 76ः भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। मधेशी मैथिली, भोजपुरी एवं हिंदी भाषा बोलते हैं मद्धेशिया के सांस्कृतिक व वैवाहिक संबंध भारतीयों से हैं। वर्ष 1964 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार मधेशी को नागरिकता के सर्टिफिकेट से वंचित कर दिया गया जिससे उन्हें नेपाल में भूमि खरीदने के अधिकारों से भी वंचित होना पड़ा। मधेशी के अनुसार मधेशी क्षेत्र का विकास नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक कम हुआ है। मधेशी यहां भी मानते हैं कि भारत की दृष्टिकोण सदैव काठमांडू केंद्रित होता है व भारत बीमा देशों के हितों की उपेक्षा करता है। नेपाल सरकार मद्धेशिया को भारत समर्थक मानती हैं।

मधेशी समस्या का भारत–नेपाल संबंधों पर प्रभाव

- मधेशी समस्याओं के अंतर्गत हिंसक गतिविधियों के कारण भारत नेपाल के बीच आवागमन मार्ग को अवरूद्ध करने से नेपाल के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि भारत के द्वारा पारा गमन मार्ग रोका गया है।
- नेपाल के द्वारा भारत के साथ संबंधों में रुचि नहीं रह गई वहीं दूसरी ओर चीन के साथ निकटता बनाने में रुचि देखी जा रही है। साथ ही नेपाल से इनके बीच रेल मार्ग बिछाने का समझौता के प्रकार से भारत की कूटनीतिक हार के रूप में देखी जा सकती।
- नेपाल के द्वारा जो भारत पर तेल भी निर्भरता ह्रास उसे समाप्त करके चीन से तेल आयात प्रारंभ कर दिया।
- भारत के द्वारा मधेसी समस्याओं को नेपाल के आंतरिक समस्याओं आपको बताया गया और यह तर्क दिया जाने लगा कि नेपाल अपने आंतरिक समस्या से ध्यान भटकाने के लिए भारत का विरोध को बढ़ावा देख रहा है। यह दोनों को लिए कटुता का प्रमाण देती है।
- वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा व वर्ष 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद भारत की ऑपरेशन मैत्री के अंतर्गत नेपाल के प्रति एक सकारात्मक रुख के रूप में देखा जा सकता है किंतु मधेसी समस्याओं के बाद नेपाल में पुनः भारत विरोध अत्यधिक प्रभावी बन गया।

वर्तमान बीजेपी सरकार व नेपाल, भारत–नेपाल संबंध का ह्रास

सितंबर 2015 में नेपाल में नया संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो गया। वह इसे लागू कर दिया गया जिनके अंतर्गत मद्धेशिया की संपूर्ण भागीदारी को नहीं स्वीकार करने के कारण भारत ने नेपाल के नए संविधान को पूर्ण रूप से स्वागत ना करने व बिग ब्रदर के रवैया को अपनाते हुए संविधान को अपूर्ण व भेदभाव से संपूर्ण संविधान करार दिया गया। जिससे भारत के द्वारा नेपाल के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप व कूटनीतिक में स्थापित करने में शीघ्रता व समर्थन देखी जा सकती है।

यदि मधेशी समय से को छोड़ दिया जाए तो यह ज्ञात होता है कि नेपाल का संविधान भारतीय संविधान से अधिक संपूर्ण है क्योंकि भारत की भांति ही नेपाल में भाषा का जाति आधारित विभित्ता विद्यमान है। वह महिलाओं के प्रति ट्रांसजेंडर, लैसबियन, बायसेक्सुअल जैसे आधुनिक समाज के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इन तथ्यों के समावेश के बावजूद भारत द्वारा नेपाल संविधान को स्वीकारना नेपाल और भारत के संबंधों का हर्ष के लिए उठाए जाने वाले कदम दिखाई देते हैं। साथ ही नेपाल द्वारा यह यह कहा जाना कि भारत के द्वारा उनको आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है परोक्ष रूप से सही दिखाई देता है।

- अंतरराष्ट्रीय संगठनों व क्षेत्रीय संगठनों मैं भी नेपाल में भारत का आपसी टकराव देखा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप भले ही नेपाल की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी एशियाई सरकार संगठन सरकार का मुख्यालय काठमांडू में ही स्थापित किया गया। इससे ना तो नेपाल सरकार को बढ़ावा मिला ना ही दक्षिणी एशियाई सरकार की गति तेज हो सके अर्थात भारत द्वारा क्षेत्रीय संगठनों में बिग ब्रदर का रवैया छोड़कर सहयोगी रवैया को अपनाया बिना संबंधों को सुधार कल्पना से बाहर है।
- भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में मामला 5 नवंबर 2015 को उठाया गया। नेपाल में बढ़ती हिंसा राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते भेदभाव की शिकायत किए तथा भारत के द्वारा ही यह बोला गया कि कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया गया। नेपाल में बढ़ती हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से लोगों को दो–चार होना पढ़ रहा है सितंबर में आए नए संविधान के बाद से हालात बद से बदतर हुए हैं।
    - इस पर नेपाल की उप प्रधानमंत्री द्वारा यह कहा जाना कि यह नेपाल को अपना संविधान अपने अनुसार लिखने का अधिकार नहीं है? यह वक्तव्य भारत द्वारा नेपाल की आंतरिक मामले में हस्तक्षेप वह नेपाल की मनोज स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
- मार्च 2018 को पाक प्रधानमंत्री शहीद अब्बासी का नेपाल यात्रा एक अन्य भारत नेपाल टकराव का जीवित उदाहरण है क्योंकि यह पहला मौका है जब नेपाल में नई सरकार का गठन के बाद वहां भारत से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दौरा रहा है एवं भारत को इसे केवल द्विपक्षीय देशों की वार्ता के रूप में ना देख कर यदि एक चेतना आदि के रूप में देखा जाए तो शायद संबंधों का हर्ष को रोका जा सकता है।

भारत और नेपाल संबंधों का वर्तमान परिदृश्य

भारत की विदेश नीति में जहां सभी देशों में अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने की अपक कोशिश की जा रही है। वही नेपाल सरकार के द्वारा भारत के प्रति अपना सही नजरिया नहीं दिखाई देता है। उत्तराखंड में काला पानी के बाद अब लिटिल एक इलाके को लेकर नेपाल में बहस तेज हो गई है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी पुष्प कमल रहता प्रचंड ने कहा कि अगर भारत कूटनीतिक तरीके से सीमा विवाद कोहल को नजर अंदाज करता है तो नेपाल फैसला करें कि उसे किस रास्ते पर बढ़ना है। भारत ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पिथौरागढ़ धारा से लिपि लेख को मोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया था उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख पर नेपाल अपना दावा करता है और उसने भारत द्वारा सड़क निर्माण के कदम का विरोध किया है। नेपाल ने रेत राम पर भारत में प्रतिक्रिया देते हुए कहा की सड़क पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में स्थित है।

नेपाल की संसद में भी लिपुलेख को लेकर टहलने सांसदों को नवाब देते हुए कहा कि समस्या का समाधान करने के लिए भारत और नेपाल को उच्च स्तरीय राजनीतिक और कूटनीतिक चौनलों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेपाल की संसदीय समिति ने भारत को लिपुलेख तक रोड लिंक खोलने के कदम को लेकर के लिए दहल को बैठक में आमंत्रित किया था।

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारत के इस कदम को एकपक्षीय बताया है। मई 2015 में भारत और चीन ने लिपुलेख से होते हुए एक व्यापार मार्ग बनाने और उसके विस्तार को लेकर मंजूरी दी थी। भारत कैलाश मानसरोवर लिंक रोड के तहत धारचूला सेल तिब्बत को जोड़ना चाहता है, जिसके लिए वह बिन बिंजिंग के संपर्क में है। दहल ने बैठक में कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल को चीन के साथ बातचीत करनी चाहिए क्योंकि अब यह 3 देशों के बीच का मामला है।

नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप गया वाली ने समस्या को बढ़ाने की तरफ बयान दिया, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध समिति को की बैठक में कहा कि भारत ने रोड लिंक बढ़ाते हुए नेपाल के 19 किलोमीटर की भूखंड पर अतिक्रमण कर लिया वही। इससे पहले भारत ने कहा था कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद नेपाल और भारत के साथ वार्ता में शामिल होगा।

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सड़क निर्माण भारत का के भूखंड क्षेत्र में ही हुआ है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर नेपाल के साथ वार्ता की जाएगी भारत के द्वारा कहा गया कि भारत नेपाल के साथ घनिष्ठ और द्विपक्षीय संबंधों की भावना और कूटनीतिक संवाद के जरिए सीमा मुद्दे को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार ने इस मुद्दे पर भारत की आलोचना की और कहा कि भारत ने इस कदम को द्विपक्षीय समझौतों और आपसी समझ दोनों का उल्लेखन हुआ है। इससे नेपाल की समस्त और उपखंड पर हल हुआ है। उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुद्दे पर भारत से बात करनी चाहिए। जबकि भारत की विदेश नीति सदैव सभी देशों की प्रमुखता एकता व अखंडता को बनाए रखने की रही है। भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ सदैव ही एल्डर ब्रदर की तरह व्यवहार किया है ना कि बिग ब्रदर की तरह

नेपाल द्वारा भारत के हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया जाना

जहां भारत सदैव सभी देशों की प्रमुखता का सम्मान करता आया है वही नेपाल अपनी हरकतों

से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल में भारत को लेकर कुछ हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया हालांकि कुछ समय पश्चात ही नेपाल ने अपने इस नक्शे को बदल दिया।

सुगौली संधि 1815

1815 मैं नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगौली संधि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुए एक युद्ध के द्वारा हार के बाद में अपालने अपना काफी सा दवा दिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद सुगौली संधि पर कंपनी की तरफ से और नेपाल की तरफ से राम गुरु गया राम ने हस्ताक्षर किए और इसी के आभार पर ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमा रेखा है। इस संधि में नेपाल की महाकाली नदी को दोनों देशों के बीच सीमा का आभार बनाया गया हालांकि पिछले 200 सालों मैं नदी में कार अपना रास्ता बदला जिसकी वजह से सीमा विवाद गहराता गया पुराने मानचित्र और दस्तावेजों की मूल प्रति ना होने की वजह से इस सीमा विवाद को सुलझाना और भी मुश्किल हो चुका है। सन 2016 में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई वार्ता के बाद इन दस्तावेजों का पता लगाने के लिए नेपाल में संसदीय मोर्चा शुरू किया गया। 22 जुलाई 1916 को मौज दल ने नेपाल की संसद में बताया कि सुगौली संधि और भारत–नेपाल संधि की मूल प्रति देशों में मौजूद नहीं है।

नेपाल की सरकारों का मपेशी समस्याओं का राजनीतिक कारण

नेपाल की सरकारों के एस मधेशी समस्या का इस्तेमाल राजनीतिक प्राधिकरण के लिए भी किया जाता है। जिस कारण यह समस्या काफी बढ़ती गई अन्यथा इससे आसानी से समझाया जा सकता था 2015 में मद्धेशिया के द्वारा रक्सौल बिहार तथा बीगुनी नेपाल ब्रिज पर आर्थिक नाकाबंदी की गई। जिस कारण नेपाल में दवाईयां मिलना बंद हो गई थी। पेट्रोल मिलना कम हुआ तथा आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई नेपाल की सरकार ने सन 2015 के आर्थिक नाकाबंदी को जोकि मदहोशियां द्वारा किया गया भारत की समीक्षा बताया तथा इसके शिक्षक के पीछे भारत का हाथ बताया नेपाल की सरकार ने मद्धेशिया को भारत के समर्थक माना नेपाल की सरकार के बारे में माना गया कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष काठमांडू सरकार का संचालन सदैव ऊपरी जाति और पहाड़ी व्यक्तियों के नेतृत्व में ही रहता है जहां मधेशी वह तरार क्षेत्रों भूमिका निरंतर पाई जाती है।

नेपाल का सीन की तरफ झुकाव

नेपाल सरकार ने चीन के साथ 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जिसके एक रेलवे लाइन और बिछाने से संबंध है तथा दूसरा टाइमिंग बोध से वस्तुओं को नेपाल पचाने के संबंधित है। हाल पीके लिपुलेख समस्या को लेकर भी नेपाल में चीन कार्ड का इस्तेमाल किया जो कि नेपाल की पुरानी आदत रही है, परंतु चीन की तरफ नेपाल का उनका हमेशा ही रहा है नेपाल की प्रमुखता के लिए खतरा संबंधित होगा। जिसका उदाहरण चीन और द्वारा श्रीलंका के अनबन तोता को आधारित करके देखा जा सकता है। चीन का यह भी प्रयास रहता है कि वह भारत की प्रगति को वंचित करने के लिए नेपाल भारत के इन पड़ोसी देशों पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका आदि का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता रहता है।

मधेशी समस्या नेपाल की आंतरिक समस्या है। जिसमें भारत को किसी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत के राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए बेवजह भारत विरोध को बढ़ावा देते हैं जबकि उन्होंने यह समझा समझाना चाहिए कि भारत एक संप्रभु देश है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पड़ोसी देशों के वजह विरोध के कारण भारत की छवि पर नकारात्मक

प्रभाव पड़ता है। नेपाल एक अभद्र देश है जिसके लिए भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही नेपाल के लिए सर्व परी बेहतर विकल्प है।

संदर्भ

- 21वी शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय संबंध – पुष्पेश पंत, पृष्ठ 118
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध– बी.एल.फाडिया, कुलदीप फाडिया, पृष्ठ 78
- भूमंडलीकरण के दौर में भारतीय विदेश नीति – राजेश मिश्रा (सरस्वती IAS), पृष्ठ 32
- दक्षिणी एशियाई देशों के राजनीति– डॉ नलिन सिंह पंवार, पृष्ठ 18